Sanskritik aur Samajik Anusandhan
www.shodhjournal.com
ISSN: 2582-5852; Impact Factor: RJIF 5.44
Received: 05-06-2020; Accepted: 20-06-2020; Published: 06-07-2020
Volume 1; Issue 2; 2020; Page No. 08-10

संकट में भारतीय जिदंगी और जीविका

Prem Prakash
HOD Department of Political Science), Radha Govind University, Ramgarh, Jharkhand, India

प्रस्तावना

इधर कुआं, उधर खाई। जान बचाएं या रोजी–रोटी? यह सवाल मध्य वर्ग के सामने अभी नहीं खड़ा है, इसीलिए वह दिल्ली के आनंद बिहार या मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जमा हुई भीड़ की लानत–मलामत कर रहा है। मगर सरकार सिर्फ मध्य वर्ग की नहीं है। वह भी यह समझती है कि अगर लॉकडाउन चलता रहा और सारे काम–धंधे बंद रखे गए, तो न सिर्फ गरीबों और मजदूरों का हाल बुरा होगा, बल्कि इसकी आंच मध्य वर्ग और फिर उच्च वर्ग तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। काम–धंधे चलेंगे नहीं, तो लोग तनख्वाह कब तक दे पाएंगे? तनख्वाह नहीं मिलेगी, कट जाएगी या नौकरी चली जाएगी। ये सारी बातें सिर्फ आशंका नहीं हैं। अपने आस–पास देखिए, यह सच्चाई दिखेगी। हो सकता है कि आपके घर के दरवाजे पर भी इसकी दस्तक सुनाई पड़ रही हो।

यही वजह है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री के सामने यह चिंता रखी कि ऐसे में लोगों की रोजी–रोटी का इंतजाम जरूरी होगा। उन्हें फिक्र भी है कि अगर सब कुछ ठप रहा, तो सरकार को टैक्स कहां से मिलेगा? और कमाई नहीं होगी, तो सरकारों वे जरूरी खर्च कहां से और कब तक करेंगी, जो इस भयानक बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी है?

जहिर है, प्रधानमंत्री ने जान भी और जहान भी का नया नारा देते हुए यह सब जरूर सोचा होगा। सरकार पर कई तरफ से दबाव भी हैं और बात में दम भी है। गांवो में किसानों का कहना था कि घर के अंदर रहने या गांव के दायरे में रहने में क्या फर्क है? अगर एक परिवार अपने खेत में जाकर फसल काटता है, उसे खलिहान तक लाता है, दाने साफ करके बेचने लायक तैयार करता है, तो इसमें हर्ज क्या है? खतरा क्या है, और इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे नहीं हो रहा है?

इसीलिए न केवल गांवो के लोग, बल्कि खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ भी सलाह दे रहे थे कि गांव के भीतर का कामकाज पूरी तरह खोल देना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को छोड़कर, जो बाहर से गांव में आ रहें हैं। बुधवार को नए नियमों के एलान के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांव जाने के इच्छुक जिन लोगों की जांच हो चुकी है, वे आइसोलेशन में रह चुके है, और उनके अंदर बीमारी का वायरस नहीं पाया गया है, ऐसे लोगों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है।

गांव हो या शहर, हर इंसान को अपनी जान की फिक्र तो है ही। लेकिन शहरों में रहते हुए, खासकर गरीब लोगों के लिए किसी से दूरी बनाकर रहना मुश्किल है। एक कोठरी में आठ–दस लोग रहते हैं। अब वे भीतर रहें, तो कैसी सोशल डिस्टेंसिंग? और बाहर निकलें, तो जाएं कहां? खासकर झुग्गी बस्तियों या जेजे कॉलोनी या एसआरए की इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए बाहर यानी बिलिडिंग–कंपाउंड में भी इतनी जगह नहीं होती कि वे एक दूसरे से बचकर निकलते रह सकें।

इस स्थिति का सबसे आसान इलाज यही दिखता है कि हर जगह कुछ न कुछ ऐसे काम शुरू हो जाएं, जिनसे इन लोगों को राहत मिल सके। और इन्हें राहत मिलने का अर्थ होगा, तमाम तरह की चाजों की सप्लाई का काम दोबारा शुरू होना। बड़ी फैक्टरियां अमूमन शहरों के बाहर ही होती हैं। लेकिन शहर बढ़ने के साथ वे उसके बीच में पहुंच जाती हैं। ऐसी जगहों पर जरूरी है कि इस वक्त कम कामगारों के साथ काम शुरू किया जाए और जितने लोग काम पर बुलाए जाए, उनके सोने, खाने

'विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़।

और नहाने का इंतजाम वहीं आसपास किया जाए, ताकि इन्हें बाहर किसी और से मिलने की जरूरत न पड़े।

लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर जो असर होने वाला है, उसके अभी तक जितने अनुमान आए है, वे सभी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि भारत की विकास दर के गिरकर 1.9 फीसदी रहने का आशंका है। इससे भी बड़ा डर यह है कि दुनिया में मंदी आने वाली है और यह 1930 की महामंदी के बाद का सबसे बड़ा संकट है। बार्कलेज का तो कहना है कि इस साल दिसंबर तक भारत की विकास दर शून्य रहेगी। लेकिन अभी तक इन आंकड़ो और अनुमानों का कोई अर्थ नहीं है। जब तक दुनिया से महामारी खत्म नहीं होगी, तब तक सही–सही हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि इससे नुकसान कितना हुआ है और कितना होगा? इसलिए यह जानना जरूरी है कि मुद्राकोष 1930 की जिस महामंदी का जिक्र कर रहा है, उसमें हुआ क्या था? उसमें दुनिया की जीडीपी 26 परसेंट से ज्यादा गिर गई थी, और करीब–करीब एक चौथाई लोगों का रोजगार चला गया था।

यहां इरादा आपको डराने का नहीं है, लेकिन पिछले महीने तक ज्यादातर लोग कह रहे थे कि मानवता के सामने यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा खतरा है। अब सब मान रहे हैं कि यह उससे कहीं बड़ा खतरा है। इसलिए जरूरी है कि महामारी के खतरे का मुकाबला करते हुए महामंदी की आशंका से निपटने की तैयारी भी साथ–साथ की जाए। सरकार ने जो फैसला किया है, वह एकदम इसी राह पर है। हां, बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। खासकर बड़े शहरों में ढील की बजाय और अधिक कड़ाई बरतनी होगी। इस वक्त लॉकडाउन के बावजूद हॉटस्पॉट बन चुके इलाकों में जो गतिविधियां है, वे खतरनाक हैं।

दूसरा जो काम बेहद जरूरी है, वह है घबराए हुए, परेशान लोगों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम। सूरत में मजदूरों का प्रदर्शन और बांद्रा की भीड़ तो बस नमूना है। देश के अलग–अलग शहरों में ऐसे हजारों लोग बेहाल फंसे हुए हैं। इनके सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। राज्य सरकारें जांच के बाद असंक्रमित लोगों को उनके घर वैसे ही

भेजें, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। इससे शहरों में भीड़ भी घटेगी और गांवो में ये ज्यादा सुरक्षित माहौल में भी होंगे।

इतिहास गवाह है कि जब भी भारत की अर्थव्यवस्था संकट में रही, तो खेती और गांव से पैदा होने वाली मांग ने ही उसे सहारा दिया है। वक्त है कि अब इस फॉमूले को पूरे जोर–शोर से लागु किया जाए। यही वह रास्ता है, जो आगे चलकर बड़े उद्यागों को चलाने और मध्य वर्ग के रोजगार को बचाने की जमीन तैयार कर पाएगा।

भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चार बार के जिस लॉकडाउन की घोषणा की थी उसकी समय सीमा खत्म होने के पहले ही उसे बढ़ाने की मांग तेज हो गई। कई मुख्यमंत्री इस पक्ष में रहे कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। मौजूदा हालात भी इसकी जरूरत रेखांकित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पांच सौ के करीब थी, लेकिन अब लाखों में पहुँच गई है। इसकी एक बड़ी वजह तब्लीगी जमात वालों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा। आंकड़े बता रहे कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या एक अप्रैल के बाद तेजी से बढ़ी। ज्ञात हो कि इसी समय तब्लीगियों को दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित उनके मरकज से बाहर निकाला गया था। उन्हें खुद को अलग–थलग रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इन्कार करने के साथ ऐसी हरकतें कीं जिससे संक्रमण तेजी से फैला। दुख, शर्म और चिंता की बात यह है कि तब्लीगियों के छिपने, असहयोग का सिलसिला अभी भी कायम है। संक्रमितों की बढ़ती इसलिए गहन चिंता का विषय है, क्योंकि भारत एक तो बड़ी आबादी वाला देश है और दूसरे उसका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पा रहा है इसलिए कोरोना की चपेट में आए लोगों की सही संख्या जानने में कठिनाई आ रही है। हैरानी नहीं कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या मौजूदा संख्या से दोगुना हो। शायद इसीलिए लॉकडाउन अवधि बढ़ाने की मांग हो रही है। यह समय की मांग है कि कोरोना प्रभावित इलाकों और खासकर शहरों में जहां सघन आबादी है वहां अधिक से अधिक संख्या में लोगों की जांच हो। जरूरी हो तो ऐसे इलाकों मं कर्फ्यू लगाकर जांच की जाए।

कोरोना का कहर देश के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहा है। दुनिया का मंदी की चपेट में आना अब एक हकीकत है। यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन की घोषणा करते समय भारत सरकार ने उद्योग–व्यापार जगत से अपेक्षा की थी कि वह अपने कर्मचारियों का वेतन न रोके, लेकिन उसके लिए वेतन को लेकर ऐसी अपेक्षा करना कठिन होगा। उद्योग–व्यापार जगत की ओर से यह अपेक्षा पूरी किया जाना आसान भी न होगा, क्योंकि हर कारोबारी इतना समर्थ नहीं कि वह बंद कारोबार के बाद भी कर्मियों के वेतन दे सके। इसी कारण लाखों लोगों की नौकरियों पर तलवार लटक गई है। यह स्थिति पूरी दुनिया में है। कोरोना के कहर से निपटने के साथ ही भारत और दुनिया के अन्य देशों को इसकी भी चिंता करनी होगी कि अर्थव्यस्था को जल्द से जल्द कैसे पटरी पर लाया जाए?

यह देखना सुखद है कि इस गहन संकट के समय विश्व भारत की ओर उम्मीदों से देख रहा है। इसका कारण प्रधानमंत्री की और से पहले सार्क और फिर जी–20 के जरिये इसके लिए सक्रियता दिखाना रहा कि कोरोना के कहर से मिलाकर कैसे निपटा जाए। भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरोना से उपजी कोविड–19 बीमारी के उपचार में सहायक मानी जाने वाली मलेरिया की दवा जिस तरह तमाम देशों को उपलब्ध कराई उससे उनके साथ–साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और अधिक निखरी है। विश्व समुदाय भारत की सराहना करने के साथ इस पर भी निगाह लगाए है कि वह कोरोना संकट से कैसे पार पाता है? स्पष्ट है कि कोरोना के कहर को थामकर भारत एक मिसाल कायम करने के साथ उन उम्मीदों को पूरा कर सकता है जो विश्व समुदाय उससे लगाए हुए है। यह मिसाल तभी कायम की जा सकती है जब संक्रमण को थामने के लिए युद्धतर पर जुटा जाए। चूंकि यह एक कठिन लड़ाई है इसलिए उसमें आम लोगों का योगदान जरूरी है।

आज जब विश्व भारत की ओर निहार रहा है तब वह चीन के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन को कठघरे में भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस संगठन ने चीन के सुर में सुर मिलाकर दुनिया को समय रहते चेताया नहीं। उसने चीन की गोद में बैठने का जो काम किया उसके कारण ही उसकी फजीहत हो रही है। यह फजीहत होनी भी चाहिए, क्योंकि उसके कारण दुनिया बहुत गहरे संकट में फंस गई है। बेहतर हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपनी गलती का अहसास हो। विश्व समुदाय को यह देखना होगा कि भविष्य में यह संगठन सही तरह काम करें।

हालांकि चीन ने कोरोना वायरस के गढ़ वुहान के लॉकडाउन को खत्म करने की घोषणा की दी, लेकिन इनमें संदेह है कि उसने महामारी बन गई कोविड–19 बीमारी पर वास्तव में काबू पा लिया है। इन दिनों तमाम वैज्ञानिक इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि कोरोना वायरस चमगादड़ या फिर पैंगोलिन के जरिये वुहान के लोगों के शरीर में आया और फिर वहां से दुनिया में फैला। कायदे से चीन को अपने लोगों को वन्य जीवों को खाने से रोकने के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने के लिए विश्व समुदाय से खेद व्यक्त करना चाहिए। एक तो इसके आसार कम है और दूसरे दुनिया यह स्मरण करने को विवश है कि इसके पहले किस तरह सार्स और एच–1एन–1 वायरस ने दुनिया पर कहर ढाया था। जैसे आज कोरोना के कारण विश्व अर्थव्यवस्था घुटनों के बल आ गई है वैसे ही सार्स एच–1 एन–1 के संक्रमण के दौरान भी उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था।

चूंकि चीन न तो लोकतांत्रिक तौर–तरीके अपनाने को तैयार है और न ही अपने सामाजिक–राजनीतिक व्यवहार को बदलने के लिए इसलिए अमेरिका, जापान समेत अन्य अनेक विकसित देश अपने करखाने चीन से बाहर लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह उचित भी है, क्योंकि इसका औचित्य नहीं कि चीन दुनिया का कारखाना बना रहे। विकसित देशों की ओर से अपने करखाने चीन से बाहर निकालने की तैयारी भारत के लिए सुनहरा अवसर है। इस अवसर को भुनाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाने चाहिए। यदि विकसित देशों के चीन में स्थापित कारखाने भारत आ सकें तो इससे देश के आर्थिक भविष्य को कहीं अधिक आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है।

आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक राहत पैकेज के पांचवे और अंतिम चरण का रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने एलान किया। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा एलान किया है, वित्त मंत्री ने कहा कि अगले एक साल तक कोई भी नयी दिवाला प्रक्रिया नहीं शुरू की जायेगी। यानी, अगले एक साल के लिए डिफॉल्ट के किसी मामले को इसके तहत नहीं लाया जायेगा। इसका बड़ा फायदा एमएसएमइ सेक्टर को मिलेगा। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए एक स्पेशल बैंकरप्सी प्रोसीजर लाया जायेगा।

अर्थव्यवस्था सुधार की बड़ी पहल

वर्तमान संकट बहुत ही गंभीर है क्योंकि यह विश्वयापी है, हमारी घरेलु अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से ही खराब थी, कोरोना महामारी की समस्या ने उसे और भी खराब हालत में पहुंचा दिया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार मुश्किल है, सो इससे हमारा निर्यात प्रभावित होगा क्योंकि वैश्विक मांग लगातार कमजोर हो रही है, यह स्थिति आनेवाले दिनों में बदतर ही होगी। रोजगार का संकट भी बढ़ता जा रहा है और लोग या औसत परिवार जो खर्च करते थे, अब वे भी बहुत संभालकर खर्च करेंगे, ऐसे मांग का स्तर कम ही होता जायेगा, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर होगा। जब भी मांग में कमी आती है और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तो यही अपेक्षा की जाती है और यही उपाय होता है कि सरकार की ओर से अपने खर्च में बढ़ोतरी की जाती

है। इससे बाजार को संभालने में मदद मिलती है, यही पहल सरकार कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिये पहले विवरण में अभिव्यक्त हुआ है, जब 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट आया था, तब भी दुनियाभर की सरकारों की ऐसी ही प्रतिक्रिया थी, पर आज का संकट हर मायने में उस स्थिति की तुलना में बहुत अधिक विकराल है क्योंकि इसका असर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीस करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसकी बहुत आवश्यकता थी, वित्त मंत्री ने इस पैकेज के कुछ अहम बिंदुओं के बारे में बताया है और अगामी दिनों में इसका पूरा ब्यौरा हमारे सामने आ जायेगा। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए तीन लाख करोड़ रूपये के कर्ज का प्रावधान बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए उद्यामियों को कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी तथा इसका जिम्मा पूरी तरह से भारत सरकार लेगी, इसके अलावा परेशानियों से घिरे ऐसे उद्यमों के लिए वित्त उपलब्ध कराया गया है, इस क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए भी दस हजार करोड़ का कोष बनाया गया है, छोटे और मझोले उद्यमों को लेकर सरकार की यह प्राथमिकता बहुत महत्वपूर्ण है, इस बारे में और अन्य छोटे–बड़े उद्योगों के लिए वित्त मुहैया कराने के बारे में जल्दी ही जानकारी मिल जायेगी। यह बहुत जरूरी है कि कारोबार को संभालने के लिऐ बाजार से महंगी दर पर कर्ज लेने की मजबूरी न हो और सरकार की ओर से कम ब्याज दर पर पैसा मिल सके ताकि वे अगले छह–सात महीने अपनी जरूरतों को पूरी कर सकें।

यह भी देखना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना निवेश करने का मन बना रही है, मांग बढ़ाने के लिए यह निवेश जरूरी है क्योंकि परियोजनाओं में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, धीरे–धीरे जब पूरा विवरण हमारे सामने होगा, तो यह कहा जा सकेगा कि पैकेज कितना अच्छा है, पर अभी तक यह कहा जा सकता है कि सरकार ने सही दिशा में सही कदम उठाया है, इससे पहले जो पैकेज दिया गया था, वह फौरी राहत के लिए था, उससे और रिजर्व बैंक द्वारा की गयी पहलों से समस्याओं का समुचित समाधान कर पाना संभव नहीं था, हालांकि वे सभी उपाय मौके के हिसाब से उचित रहे है, रिजर्व बैंक के उपाय ज्यादातर बैंकिग सेक्टर में राहत देने से संबंधित है, व्यक्तिगत या कंपनियों के कर्ज को चुकाने या नगदी मुहैया कराने में हो रही परेशानियों के तात्कालिक समाधान के उद्देश्य से वे कदम उठाये गये है, कोरोना संकट का असर कई स्तरों पर है, छोटे और मझोले उद्यमों में कार्यरत कामगर संगठित या औपचारिक क्षेत्र के हिस्से नहीं होते है, इस सेक्टर का कारोबार बहुत हद तक नगदी के लेने–देन पर निर्भर करता है, जब भी कोई आर्थिक संकट आता है, छोटे और मझोले उपक्रम तुरंत मुश्किलों से घिर जाते है इन्हें बैंको, बजारों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने में भी बहुत परेशानी होती है, जबकि संगठित उद्योग आसानी से जरूरत की नगदी जुटा लेते हैं क्योंकि उनके पास गारंटी के रूप में परिसंपत्तियां होती है, हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 60 फीसदी असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है और इसी क्षेत्र पर ही निर्भर है और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार भी मिलता है, इसलिए ऐसे उद्यमों को संभालने के बिना अर्थव्यस्था को ठीक नहीं किया जा सकता है, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अभियान में छोटे और मध्यम उद्यमों को प्राथमिकता देना बहुत सराहनीय निर्णय है, उम्मीद कि आगामी घोषणाओं में और अनेक उपायों की जानकारी दी जायेगी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एक अहम बात यह कही है कि हम आत्मनिर्भर होना है, अब सरकार का ध्यान स्थानीय उद्योगों और मेक इन इंडिया पर अधिक होगा। चीन जैसे देशों में, जो बड़े मैनुफैक्चरिंग हब बने है और जहां से हम भी बहुत सारा सामान आयात करते है, छोटे और मझोले उद्यम ही आधार है। हमारे सामने एक चुनौती सप्लाई चेन को लेकर है, जिस पर मौजूदा संकट का असर पड़ा है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र को लें। उसकी ऊपज और पैकेज्ड फूड बनाने तक की प्रक्रिया को फिर से बहाल करने पर जोर देना होगा। हमें यह भी समझना चाहिए कि बड़े उद्योगों का सप्लाई चेन भी काफी हद तक छोटे मझोले उद्यमों पर निर्भर करता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि बीस लाख करोड़ रूपये का यह पैकेज कई स्तरों पर अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से गतिशील करने के उद्देश्य से लाया गया है। यही आज की जरूरत है।

कई उत्पादों के लिए भारत समेत दुनियाभर की बहुत अधिक निर्भरता चीन के ऊपर अब तक थी। कोरोना संकट ने यह अहसास दिला दिया है कि अगर आप एक ही जगह निर्भर रहेंगे, तो किसी आपदा की स्थिति में आपके उद्योग और कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो सकते है। इसलिए उत्पादन को कई देशों में विकेंद्रित करने की दिशा में सोचना पड़ेगा। ऐसे में ज्ञापन, यूरोप और अमेरिका जैसे क्षेत्रों से भारत में निवेश की संभावनाएं बढ़ गयी है, यह भारत के लिए एक अवसर है, जिसका संकेत प्रधानमंत्री ने किया है। अभी तक दुनिया में मुक्त व्यापार की व्यवस्था रही है, अब कुछ हद तक स्थानीय स्तर पर उत्पादन का अवसर है और इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। विदेश से आयात पर निर्भरता में कमी करने की दिशा में पहल जरूरी है और इसका कुछ इशारा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के संबोधनों में है। अब मामला इन फैसलों को सही तरह से अमल में लाने की है।

संदर्भ सूची

1. आलोक जोशी – हिन्दुस्तान (संपादकीय) 16 अप्रैल 2020, पृ0सं0 – 08
2. संजय गुप्त – जागरण (संपादकीय) 12 अप्रैल 2020, पृ0सं0– 06
3. समाचार – प्रभात खबर (संपादकीय) 18 मई 2020, पृ0सं0– 09
4. प्रीतम बनर्जी – प्रभात खबर (संपादकीय) 14 मई 2020, पृ0सं0– 06